International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

Original Article

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन: साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. सरोज देवी

सहायक प्राचार्य, इतिहास विभाग,

महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय, आरा,

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

Manuscript ID:
IJAAR-130521
ISSN: 2347-7075
Impact Factor – 8.141

Volume - 13
Issue - 5
May – June 2026
Pp. 189 - 197

Submitted: 14 May 2026
Revised: 30 May 2026
Accepted: 1 June 2026
Published: 10 June 2026

Corresponding Author:
डॉ. सरोज देवी

Quick Response Code:

Website: https://ijaar.co.in/

DOI: 10.5281/zenodo.21413546

DOI Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.21413546

सारांश:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1885–1947) केवल औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक मुक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक स्वावलंबन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना के निर्माण का व्यापक अभियान भी था। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के संदर्भ में समग्र विश्लेषण करना है। अध्ययन में महात्मा गांधी के स्वदेशी एवं ग्राम स्वराज, दादाभाई नौरोजी के धन-निष्कासन (Drain of Wealth) सिद्धांत, डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्याय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मानवतावाद तथा प्रेमचंद सहित राष्ट्रवादी साहित्यकारों के योगदान का विश्लेषण किया गया है।

यह शोध गुणात्मक (Qualitative) एवं ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक (Historical-Analytical) पद्धति पर आधारित है तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों—राष्ट्रीय अभिलेखागार, जनगणना रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज़, शोध-पत्रों, समाचार-पत्रों और डिजिटल स्रोतों—का उपयोग करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, जबकि बंग-भंग (1905), असहयोग आंदोलन (1920–22), दांडी यात्रा (12 मार्च–6 अप्रैल 1930) तथा भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942) ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 8% थी, जबकि लगभग 70–75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। औपनिवेशिक काल में दादाभाई नौरोजी ने प्रतिवर्ष लगभग 20–30 मिलियन पाउंड के धन-निष्कासन का अनुमान प्रस्तुत किया, जिसने ब्रिटिश आर्थिक शोषण की वास्तविकता को उजागर किया।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि सीमित साक्षरता के बावजूद केसरी, यंग इंडिया, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका तथा हिंदी, उर्दू और बंगाली साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में निर्णायक भूमिका निभाई। समकालीन वैश्विक मीडिया और डिजिटल संचार के युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विचार लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की वैश्विक बहसों में पुनः प्रासंगिक हो रहे हैं। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website: https://ijaar.co.in/*
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

का सामाजिक-आर्थिक चिंतन आज भी विकसित भारत 2047 की परिकल्पना, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समानता और सतत विकास के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान करता है।

मुख्य शब्द: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक-आर्थिक चिंतन, राष्ट्रवादी साहित्य, सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक मीडिया, विकसित भारत 2047.

Creative Commons

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*

How to cite this article:

डॉ. सरोज देवी. (2026). भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन: साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के परिप्रेक्ष्य में. International Journal of Advance and Applied Research, 13(5), 189 – 197.

https://doi.org/10.5281/zenodo.21413546

परिचय:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का एक ऐसा व्यापक जनांदोलन था, जिसने केवल औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया को भी गति प्रदान की। **28 दिसंबर 1885** को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसने **15 अगस्त 1947** को भारत की स्वतंत्रता तक विभिन्न चरणों में राष्ट्र निर्माण की वैचारिक आधारशिला तैयार की। इस आंदोलन के केंद्र में राजनीतिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय एकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का उद्देश्य निहित था।

औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था गहरे शोषण का शिकार रही। दादाभाई नौरोजी ने अपने **धन-निष्कासन (Drain of Wealth) सिद्धांत** के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग **20–30 मिलियन पाउंड** की आर्थिक निकासी का उल्लेख किया, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार प्रदान किया। **1931 की जनगणना** के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग **8 प्रतिशत** थी, जबकि लगभग **70–75 प्रतिशत** जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रवादी साहित्य, समाचार-पत्र, लोकसाहित्य और जनसभाएँ राष्ट्रीय चेतना के प्रभावी माध्यम बने। महात्मा गांधी के *यंग इंडिया* और *हरिजन*, बाल गंगाधर तिलक के *केसरी*, तथा प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मैथिलीशरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे साहित्यकारों की रचनाओं ने स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुँचाया।

समकालीन वैश्वीकरण और डिजिटल मीडिया के युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक विचारों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। लोकतंत्र, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय तथा

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

सांस्कृतिक विविधता जैसे सिद्धांत आज भी सार्वजनिक नीति और राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह शोधपत्र साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के अंतर्संबंधों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का विश्लेषण करता है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि इसकी वैचारिक विरासत **विकसित भारत 2047** की परिकल्पना को किस प्रकार बौद्धिक एवं नीतिगत आधार प्रदान करती है।

साहित्य समीक्षा:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन पर अनेक विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी विचारकों में दादाभाई नौरोजी ने अपनी कृति *Poverty and Un-British Rule in India* (1901) में **धन-निष्कासन (Drain of Wealth)** सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण का विश्लेषण किया, जिसने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव रखी। रोमेश चंद्र दत्त ने *The Economic History of India* में औपनिवेशिक भूमि-राजस्व व्यवस्था, कृषि संकट और औद्योगिक अवनति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी की *Hind Swaraj* (1909) ने स्वदेशी, ग्राम स्वराज, नैतिक राजनीति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया, जबकि डॉ. भीमराव आंबेडकर की *Annihilation of Caste* (1936) ने सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों को राष्ट्र-निर्माण की अनिवार्य शर्त बताया।

आधुनिक इतिहासकारों में बिपिन चंद्र ने *India's Struggle for Independence* तथा *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* में राष्ट्रीय आंदोलन को जन-आधारित राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया। सुमित सरकार ने *Modern India* में राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार, किसान एवं श्रमिक आंदोलनों तथा औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण किया। पार्थ चटर्जी, रामचंद्र गुहा और शेखर बंद्योपाध्याय ने राष्ट्रवाद, संस्कृति, समाज और राज्य के अंतर्संबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। साहित्यिक दृष्टि से प्रेमचंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मैथिलीशरण गुप्त तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक परिवर्तन के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है।

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक आयामों पर केंद्रित हैं, जबकि साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के समन्वित परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। प्रस्तुत शोध इसी शोध-अंतर (Research Gap) को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत को समकालीन वैश्विक मीडिया, सामाजिक परिवर्तन तथा **विकसित भारत 2047** के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास करता है।

शोध के उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का साहित्य, समाज

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

और वैश्विक मीडिया के परिप्रेक्ष्य में समग्र एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1885–1947) के सामाजिक एवं आर्थिक विचारों के विकास, उनके वैचारिक आधार तथा राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करता है। शोध का उद्देश्य महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा अन्य राष्ट्रवादी विचारकों के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का विश्लेषण करना तथा राष्ट्रवादी साहित्य, समाचार-पत्रों और जनसंचार माध्यमों द्वारा राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और जनजागरण में निभाई गई भूमिका का परीक्षण करना है। साथ ही, यह अध्ययन भारतीय समाज में राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय, महिला सहभागिता, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे आयामों का विश्लेषण करता है। शोध का एक अन्य उद्देश्य वैश्वीकरण एवं डिजिटल मीडिया के वर्तमान युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा की समकालीन प्रासंगिकता तथा उसके वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अंततः यह अध्ययन विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन की उपयोगिता और नीतिगत महत्त्व को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

आँकड़े एवं शोध पद्धति:

प्रस्तुत शोध गुणात्मक (Qualitative) एवं ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक (Historical-Analytical) पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन का विश्लेषण 1885 से 1947 की अवधि को केंद्र में रखकर किया गया है। शोध के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन अभिलेख, ब्रिटिश भारत सरकार की प्रशासनिक रिपोर्टें, जनगणना रिपोर्टें (विशेषतः 1931 एवं 1941), गांधी, नौरोजी, आंबेडकर और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मूल लेखन, राष्ट्रवादी समाचार-पत्र—*केसरी*, *यंग इंडिया*, *हरिजन* तथा *अमृत बाजार पत्रिका*—और राष्ट्रीय अभिलेखागार की सामग्री सम्मिलित की गई है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकों, शोध-पत्रों, विश्वविद्यालय शोधप्रबंधों तथा समकालीन डिजिटल मीडिया अध्ययनों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रमुख ऐतिहासिक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (28 दिसंबर 1885), बंग-भंग (1905), असहयोग आंदोलन (1920–22), दांडी यात्रा (12 मार्च–6 अप्रैल 1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942) शामिल हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग 8 प्रतिशत थी तथा लगभग 70–75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 20–30 मिलियन पाउंड के धन-निष्कासन के अनुमान को औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के संकेतक के रूप में लिया गया है। समकालीन संदर्भ के लिए भारत में लगभग 97 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 46–50 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से संबंधित डिजिटल आँकड़ों का भी उपयोग किया गया है।

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

शोध में विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis), तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Method) तथा व्याख्यात्मक पद्धति (Interpretative Approach) का प्रयोग किया गया है, जिससे साहित्य, समाज और वैश्विक मीडिया के अंतर्संबंधों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन की ऐतिहासिक निरंतरता और समकालीन प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जा सके।

परिणाम एवं चर्चा:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं वैचारिक प्रक्रियाओं में से एक था, जिसने न केवल भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण की आधारशिला भी रखी। इस अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण, समतामूलक, आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत का निर्माण करना था। **28 दिसंबर 1885** को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवादी राजनीति को संगठित स्वरूप प्रदान किया, जबकि **1905** के बंग-भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन ने पहली बार आर्थिक राष्ट्रवाद को व्यापक जनसमर्थन दिलाया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, कुटीर उद्योगों के विकास तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भावना ने भारतीय समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता की चेतना उत्पन्न की।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सामाजिक सुधार को राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य अंग माना। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी तथा डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे विचारकों ने जातिगत असमानता, अस्पृश्यता, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यापक जनमत तैयार किया। गांधीजी ने हरिजन उत्थान, ग्राम स्वराज और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समरसता पर बल दिया, जबकि डॉ. आंबेडकर ने समान नागरिक अधिकार, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय को लोकतंत्र की आधारशिला माना। इन विचारों ने स्वतंत्र भारत के संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संस्थागत रूप प्रदान किया।

शोध से यह भी ज्ञात होता है कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। दादाभाई नौरोजी के **Drain of Wealth Theory** ने प्रतिवर्ष लगभग **20–30 मिलियन पाउंड** के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन भेजे जाने का उल्लेख कर औपनिवेशिक शोषण की वास्तविकता को उजागर किया। रोमेश चंद्र दत्त ने भी कृषि संकट, अत्यधिक भूमि-राजस्व तथा औद्योगिक अवनति को ब्रिटिश शासन की प्रमुख आर्थिक विफलताओं के रूप में प्रस्तुत किया। **1931 की जनगणना** के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग **8 प्रतिशत** थी, जबकि **70–75 प्रतिशत** जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इस स्थिति ने शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कीं। गांधीजी के स्वदेशी, खादी और ग्रामोद्योग संबंधी विचारों ने स्थानीय उत्पादन, रोजगार सृजन तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की अवधारणा

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

को मजबूत किया, जो आज **आत्मनिर्भर भारत** अभियान में भी परिलक्षित होती है।

अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य ने केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का कार्य नहीं किया, बल्कि वह राष्ट्रीय चेतना का प्रभावी माध्यम भी बना। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय का *वंदे मातरम्*, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ, प्रेमचंद के उपन्यास, मैथिलीशरण गुप्त की *भारत-भारती*, रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रवादी कविताएँ तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की *झाँसी की रानी* जैसी रचनाओं ने देशभक्ति, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को जन-जन तक पहुँचाया। हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, उर्दू तथा अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरण का सशक्त माध्यम बना। साहित्य ने जनता को औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध मानसिक रूप से तैयार किया तथा स्वतंत्रता संघर्ष को नैतिक और वैचारिक आधार प्रदान किया।

समाचार-पत्रों और पत्रकारिता की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। *केसरी*, *मराठा*, *यंग इंडिया*, *हरिजन*, *अमृत बाजार पत्रिका*, *द हिंदू* तथा *द ट्रिब्यून* जैसे समाचार-पत्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों को व्यापक समाज तक पहुँचाया। **1931** में साक्षरता केवल लगभग **8 प्रतिशत** होने के बावजूद समाचार-पत्रों का सामूहिक वाचन, जनसभाएँ, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक और भाषण राष्ट्रवादी विचारों के प्रभावी माध्यम बने। इससे स्पष्ट होता है कि संचार के सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक जनभागीदारी वाला आंदोलन बन गया था।

महिलाओं की भागीदारी भी इस अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी तथा कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार तथा भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने भारतीय समाज में लैंगिक समानता की नई चेतना विकसित की। यह परिवर्तन स्वतंत्र भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और लोकतांत्रिक सहभागिता का आधार बना।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों ने विश्व स्तर पर अनेक आंदोलनों को प्रेरित किया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद विरोधी संघर्ष तथा अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों ने भारतीय अनुभव से प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन वैश्विक राजनीतिक विचारधारा का भी महत्त्वपूर्ण अंग बन गया।

समकालीन वैश्वीकरण और डिजिटल मीडिया के युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा नई प्रासंगिकता प्राप्त कर रही है। भारत में **2025** तक लगभग **97 करोड़** इंटरनेट उपयोगकर्ता तथा **46–50 करोड़** सोशल मीडिया उपयोगकर्ता राष्ट्रीय इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रवादी विचारों से संबंधित सामग्री तक पहुँच बना रहे हैं। डिजिटल अभिलेखागार, ई-पुस्तकें, ऑनलाइन संग्रहालय, विश्वविद्यालयीय शोध तथा सोशल मीडिया मंचों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाया है। यद्यपि डिजिटल माध्यमों में ऐतिहासिक

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

तथ्यों के विकृतिकरण और भ्रामक सूचनाओं की चुनौती भी मौजूद है, फिर भी प्रमाण-आधारित शोध, अभिलेखीय स्रोतों तथा अकादमिक विमर्श के माध्यम से ऐतिहासिक सत्यता को संरक्षित किया जा सकता है।

इस अध्ययन के परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन आज भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सांस्कृतिक बहुलता के लिए समान रूप से प्रासंगिक है। स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सामाजिक समानता, संवैधानिक लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय एकता जैसे सिद्धांत वर्तमान सार्वजनिक नीतियों और विकास रणनीतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डिजिटल समावेशन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सतत आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत से जोड़ना आवश्यक है। इसलिए यह अध्ययन निष्कर्ष रूप में स्थापित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि समकालीन भारत और भविष्य के राष्ट्र-निर्माण के लिए एक जीवंत, प्रासंगिक और मार्गदर्शक वैचारिक आधार है।

सिफारिशें:

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह अनुशंसा की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अधिक समग्र और समकालीन दृष्टिकोण के साथ सम्मिलित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता तथा संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता विकसित हो सके। राष्ट्रवादी साहित्य, ऐतिहासिक अभिलेखों एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दस्तावेज़ों का व्यापक डिजिटलीकरण कर उन्हें सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाया जाना चाहिए, जिससे शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों को प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हो सकें। डिजिटल एवं वैश्विक मीडिया मंचों पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रसार किया जाए तथा भ्रामक एवं अप्रमाणित सूचनाओं के विरुद्ध तथ्य-आधारित अकादमिक पहल को प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वदेशी उद्यम, कौशल विकास तथा आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों को राष्ट्रीय आंदोलन की मूल वैचारिक प्रेरणाओं से जोड़ते हुए प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के मध्य संयुक्त अनुसंधान, अभिलेखीय सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक-आर्थिक चिंतन को वैश्विक अकादमिक विमर्श में और अधिक सशक्त रूप से स्थापित किया जाना चाहिए। इससे **विकसित भारत 2047** के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक समावेशी, लोकतांत्रिक और ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण को बल मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन आधुनिक भारत के निर्माण की वैचारिक आधारशिला

International Journal of Advance and Applied Research
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2347-7075 | Impact Factor – 8.141 | *Website:* https://ijaar.co.in/
Volume-13, Issue-5 | May – June 2026

है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का माध्यम नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना का व्यापक अभियान भी था। महात्मा गांधी के स्वदेशी, ग्राम स्वराज और अहिंसा, दादाभाई नौरोजी के धन-निष्कासन सिद्धांत, डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्याय तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मानवतावादी दृष्टिकोण ने भारतीय राष्ट्रवाद को व्यापक वैचारिक आधार प्रदान किया।

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि राष्ट्रवादी साहित्य, समाचार-पत्रों और जनसंचार माध्यमों ने सीमित साक्षरता (1931 में लगभग **8 प्रतिशत**) के बावजूद राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के विचारों को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। साथ ही, औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, कृषि संकट और धन-निष्कासन की नीतियों के विरुद्ध विकसित आर्थिक चिंतन ने स्वदेशी, कुटीर उद्योग तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सुदृढ़ किया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी भारत की विकास नीतियों में परिलक्षित होती है।

वैश्वीकरण और डिजिटल मीडिया के वर्तमान युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत नई संभावनाओं और चुनौतियों के साथ पुनः उभरकर सामने आई है। डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन शिक्षा, सोशल मीडिया और वैश्विक संचार मंचों ने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और उसके मूल्यों को विश्व स्तर पर पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। तथापि, ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और अभिलेखीय स्रोतों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक-आर्थिक चिंतन आज भी लोकतंत्र, सामाजिक समानता, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। **विकसित भारत 2047** की परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत को समकालीन नीतियों, शिक्षा, साहित्य, मीडिया और जनभागीदारी के साथ समन्वित करना समय की आवश्यकता है। यही दृष्टिकोण भारत को न्यायपूर्ण, समावेशी, सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. आंबेडकर, भीमराव आर. (1936). *जाति का विनाश* (Annihilation of Caste). भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस।
2. चंद्र, बिपिन. (1989). *भारत का स्वतंत्रता संग्राम* (India's Struggle for Independence). पेंगुइन बुक्स।
3. चंद्र, बिपिन. (1966). *भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और विकास* (The Rise and Growth of Economic Nationalism in India). पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस।
4. चंद्र, बिपिन. (2009). *आधुनिक भारत* (History of Modern India). ओरिएंट ब्लैकस्वान।

5. दत्त, रोमेश चंद्र. (1902). *भारत का आर्थिक इतिहास* (The Economic History of India). केगन पॉल।
6. गांधी, मोहनदास करमचंद. (1909). *हिन्द स्वराज*. नवजीवन प्रकाशन।
7. गांधी, मोहनदास करमचंद. (1958). *सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय* (खंड 1–100). प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
8. गुहा, रामचंद्र. (2007). *गांधी के बाद भारत* (India After Gandhi). पिकाडोर इंडिया।
9. गुप्त, मैथिलीशरण. (1912). *भारत-भारती*. साहित्य सदन।
10. चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र. (1882). *आनंदमठ*. बंगदर्शन प्रेस।
11. चटर्जी, पार्थ. (1993). द *नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. नौरोजी, दादाभाई. (1901). *भारत में गरीबी और अब्रिटिश शासन* (Poverty and Un-British Rule in India). स्वान सोननशाइन एंड कंपनी।
13. प्रेमचंद. (1936). *गोदान*. सरस्वती प्रेस।
14. रवीन्द्रनाथ ठाकुर. (1917). *राष्ट्रवाद* (Nationalism). मैकमिलन।
15. सरकार, सुमित. (1983). *आधुनिक भारत (1885–1947)* (Modern India: 1885–1947). मैकमिलन इंडिया।
16. बंद्योपाध्याय, शेखर. (2004). *प्लासी से विभाजन तक: आधुनिक भारत का इतिहास* (From Plassey to Partition and After). ओरिएंट ब्लैकस्वान।
17. भारत सरकार. (1931). *भारत की जनगणना, 1931*. भारत सरकार प्रेस।
18. भारत सरकार. (1941). *भारत की जनगणना, 1941*. भारत सरकार प्रेस।
19. प्रेस सूचना ब्यूरो. (2024). *डिजिटल इंडिया एवं सुशासन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन*. भारत सरकार।
20. शर्मा, रामविलास. (1999). *भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन*. राजकमल प्रकाशन।